

दैनिक जागरण

अपनी प्रसन्नता के निर्धारक आप स्वयं होते हैं

गैर जिम्मेदार ईरान

आखिरकार ईरान अपनी उस गलती को स्वीकार करने के लिए बाध्य हुआ जिससे वह इन्कार कर रहा था। निःसंदेह उसने ऐसा इसीलिए किया, क्योंकि इसके सुवृत्त सामने आने लगे थे कि यूक्रेन का यात्री विमान उसकी मिसाइल का ही निशाना बना। इस विमान में चालक दल के सदस्यों सहित 176 लोग सवार थे। इनमें से 80 से अधिक यात्री तो ईरान के ही थे। साफ है कि बदले की आग में जलते ईरान ने उन निर्दोष लोगों की बलि ले ली जिनका उसके और अमेरिका के बीच जारी टकराव से कहीं कोई लेना-देना नहीं था। यह मानवीय भूल नहीं अक्षम्य लापरवाही है। भले ही ईरान ने इस यात्री विमान को निशाना बनाए जाने के लिए माफी मांगी हो, लेकिन उसकी ओर से जिस तरह यह कहा गया कि यूक्रेन का विमान कथित तौर पर संवेदनशील क्षेत्र की ओर मुड़ रहा था उससे यही पता चलता है कि वह अपनी भीषण लापरवाही पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। इस कोशिश को बेनकाब किया जाना चाहिए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि ईरान ने बेहद गैर जिम्मेदाराना हरकत को अंजाम दिया और फिर उसे मानवीय भूल के आवरण से ढकने में जुटा। इस तरह के स्पष्टीकरण को हस्त्यास्पद ही कहा जाएगा कि ईरानी सेना ने यात्री विमान को कूज मिसाइल समझ लिया।

आखिर जिस देश की सेना यात्री विमान और कूज मिसाइल में भेद करना न जानती हो उसे परमाणु हथियार से लैस होने की इजाजत कैसे दी जा सकती है? ईरान ने यात्री विमान को निशाना बनाकर तो यही रेखांकित किया कि वह परमाणु हथियार हासिल करने का हकदार बिल्कुल नहीं है। बेहतर यह कि ईरान की इस कथित मानवीय भूल का संज्ञान संयुक्त राष्ट्र भी ले। उसे न केवल ईरान को इस हदसे के लिए जवाबदेह बनाना होगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना होगा कि दुनिया के अशांत क्षेत्रों में इस तरह की गफलत न होने पाए। उद्घरण क्षेत्र के विशेषज्ञों ने ईरान से यह जो सवाल पूछा है कि आखिर जब वह इराक में अमेरिका के सैनिक टिकानों पर मिसाइल हमले की तैयारी कर रहा था तो फिर उसने अपने हवाई क्षेत्र को प्रतिबंधित करना जरूरी क्यों नहीं समझा उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। किसी भी जिम्मेदार देश से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी सैन्य गतिविधियों को संचालित करते समय यात्री विमानों के सुरक्षित संचालन की चिंता करे और आवश्यक समझे तो उनकी उड़ान पर रोक लगा दे। चूंकि ईरान ने यह बुनियादी काम नहीं किया इसलिए 176 लोग जान से हाथ धो बैठे। इस त्रासदी के बाद यह जरूरी है कि दुनिया भर की एयरलाइंस और अधिक सतर्क हो जाएं।

चिंताजनक संकेत

भले ही हिमाचल प्रदेश भौगोलिक रूप से छोटा राज्य है, लेकिन बहलदुरी में यह देश के लिए मिसाल है। गर्व की बात है कि यहाँ के चार जांबाजों को सेना का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र मिला है। इसके अलावा सेना के अन्य सम्मान भी यहाँ के जांबाज समय-समय पर हासिल करते रहे हैं। भारतीय सैन्य अकादमी में भी प्रदेश के युवा अपनी प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन कर सेना की विभिन्न इकाइयों में सेवाएँ दे रहे हैं। यह देश प्रेम का जन्मा है कि जब प्रदेश में कहीं भी सेना की भर्ती होती है तो युवाओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। सेना में अफसर ही नहीं सिपाही देने में भी हिमाचल हमेशा अग्रणी रहा है। हिमाचल के प्रत्येक गाँव और हर दूसरे घर से जवान सेना में सेवाएँ दे रहा है, लेकिन अब चिंता यह है कि पहाड़ के युवा मैदान में हॉफने लगे हैं। उनका में जारी भर्ती रैली में भी सामने आया है कि भर्ती होने आए युवाओं में से सिर्फ दस फीसद ही मैदान की परीक्षा पास कर पाए हैं यानी दौड़ में ही हॉफ गए।

इसका एक कारण सही खानपान न होना तो है ही, लेकिन बड़ती नशाखोरी भी बड़ा कारण है। युवाओं के दमखम में आई कमी की एक वजह खेल गतिविधियों में शामिल न होना और मोबाइल इत्यादि में खोया रहना भी है। एक दौर था जब खेत-खलिहानों में भी युवा खेलते देखे जाते थे, लेकिन अब अधिकतर युवा बंद कमरों में इंटरनेट में ही व्यस्त रहते हैं। यह भी सही है कि प्रदेश में सेना भर्ती के लिए कोचिंग सेंटर के अलावा शहरों व कस्बों में जिम भी खोले गए हैं। सरकारी स्तर पर भी बच्चों को सशक्त बनाने के लिए खेलों व शारीरिक विकास के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, लेकिन पुलिस, वन विभाग व सेना की भर्ती में युवाओं का मैदान टेस्ट पास न कर पाना गंभीर मामला है। यह बात सभी को समझनी होगी कि युवा ही कल का भविष्य हैं। अगर ये स्वस्थ व सशक्त होंगे, तभी राष्ट्र मजबूत हो सकेगा। मजबूत व सशक्त युवाओं के लिए समाज के हर वर्ग की जिम्मेदारी है। सबसे जरूरी है कि युवाओं को गलत राह पर जाने से रोका जाए। नशे के खिलाफ प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होना होगा। सरकारी स्तर पर प्रयास भी तभी सफल होंगे, जब सभी लोग इसके खिलाफ एकजुट होंगे। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस मामले में प्रत्येक स्तर पर गंभीरता देखने को मिलेगी। एकजुट प्रयासों से ही इसमें सफलता सुनिश्चित हो सकेगी।

सेना की भर्ती रैली में सामने आया है कि दस फीसद युवा ही दौड़ में तय लक्ष्य हासिल कर पा रहे हैं, यह चिंता के साथ संभलने का मौका इसलिए है, क्योंकि इससे सबक लेकर स्थिति को सुधारा जा सकता है



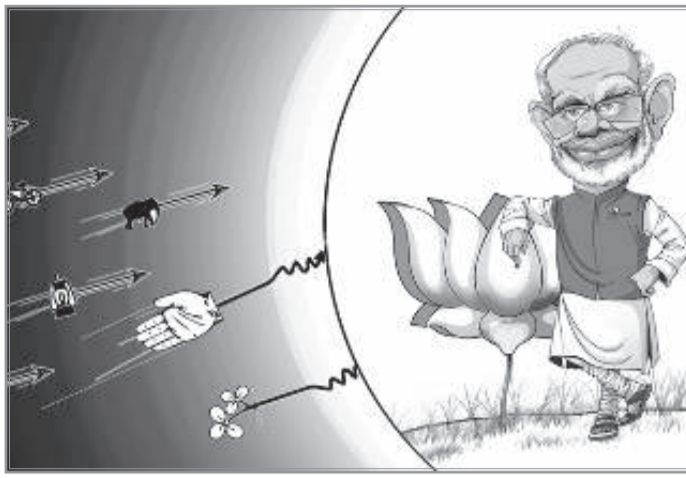
संजय गुप्त

विपक्ष को इसका आभास हो तो बेहतर कि मोदी सरकार अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध है और अतार्किक विरोध उसे फायदा ही पहुंचा रहा है

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में नकाब पहने लोगों ने जिस तरह छात्रों को लाठी-डंडों से पीटा और तोड़फोड़ की उसकी जितनी भी निंदा-भर्त्सना की जाए, कम है। इन नकाबपोश हमलावरों की पहचान करके उन्हें सख्त सजा दी जानी चाहिए। सजा के हकदार वे छात्र भी हैं जो करीब तीन महीनों से विश्वविद्यालय में पठन-पाठन बाधित किए हुए थे और अपनी मांगों मनवाने के लिए हिंसा का सहारा भी ले रहे थे। इन छात्रों ने नए छात्रों का रजिस्ट्रेशन में रोकने के लिए विश्वविद्यालय के सर्वर रूप में जाकर जिस तरह तोड़फोड़ की उसे भी गुंडागर्दी के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। किसी भी विश्वविद्यालय में कोई भी विवाद हो उसे हिंसा के जरिये सुलझाने की कोशिश करना अतिवादी कृत्य है। इस अतिवाद से केवल वैमनस्य ही बढ़ेगा और समस्याएँ और अधिक विकराल होंगी। गांधी और आंबेडकर के देश में विश्वविद्यालय परिसर में हिंसक घटनाएँ होना खतरनाक है। दिल्ली पुलिस ने अपनी प्रारंभिक जांच में हिंसा करने वाले करीब दस छात्रों की पहचान की है। इनमें दोनों यानी वाम और दक्षिणपंथी गुट के छात्र हैं। एक नाम छात्रसंघ की अध्यक्ष का भी है। इस पर हैरानी नहीं कि जेएनयू हिंसा की भी वैसी ही मनमानी व्याख्या की जा रही है जैसी नागरिकता संशोधन कानून को लेकर की जा रही है। इसमें संदेह है कि विपक्ष के ऐसे आचरण से

मोदी सरकार को सेहत पर कोई असर पड़ने वाला है। वैसे भी उसका एजेंडा साफ है और उसके तहत वह देश की पुरानी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। विपक्ष को इसका आभास हो तो बेहतर कि दूसरे कार्यकाल में मोदी सरकार अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए कहीं अधिक संकल्पबद्ध है और उसका बेजा विरोध उसे फायदा ही पहुंचा रहा है।

इस कानून के खिलाफ खड़े राजनीतिक दलों ने सरकार विरोध के अपने अभियान में जिस तरह जेएनयू हिंसा को भी धुनाया शुरू कर दिया है उससे यदि कुछ साफ हो रहा तो यही कि उन्हें मोदी सरकार के विरोध का कोई न कोई बहाना चाहिए। यदि ऐसे राजनीतिक और साथ ही गैर राजनीतिक तत्व यह समझ रहे हैं कि अपने अतार्किक विरोध से वे मोदी सरकार को दबाव में ले आएंगे तो इसका मतलब यही है कि उन्हें इसका भान ही नहीं कि यह सरकार अपने एजेंडे से इस तरह पीछे हटने वाली नहीं है। इसका प्रमाण केवल यही नहीं कि उसने ताम्र विरोध को दरकिनार कर विगत दिवस नागरिकता संशोधन कानून को अधिसूचित कर दिया, बल्कि यह भी है कि उसने तीन तलाक विधेयक को कानून का रूप देने के अपने संकल्प को पूरा किया और कर्त्तरी से अनुच्छेद 370 हटाने के असंभव लक्ष्य को भी पूरा किया। साफ है कि विपक्षी दल या तो मोदी और शाह के इरादों से अनजान है या फिर यह समझने से



अवधेश राजपूत

इन्कार कर रहे कि राष्ट्रीय महत्व के मसलों पर उनका अनावश्यक विरोध कर वह उन्हें ही राजनीतिक रूप से मजबूत करने का काम कर रहे हैं।

जहां तक जेएनयू की बात है, यह विश्वविद्यालय अपनी विशिष्ट वामपंथी संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहां वामपंथी संस्कृति को पोषण इसलिए मिला, क्योंकि वामपंथियों को खुश करने के लिए ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस विश्वविद्यालय में वामपंथी विचारकों को चुन-चुनकर रखा गया इसलिए वह वामपंथ का अड्डा बन गया। यह उस दौर में हुआ जब भारत तत्कालीन सोवियत संघ के पाले में दिखता था। चूंकि इंदिरा गांधी ने जेएनयू के जरिये वामपंथियों के मन की मुगद पूरी की इसलिए आपातकाल के दौरान उन्होंने भी उनका साथ दिया। चूंकि जेएनयू में वामपंथी सोच-विचार को संरक्षित करने का सिलसिला दशकों तक कायम रहा इसलिए वाम दलों और छात्र संगठनों ने इस विश्वविद्यालय को

अपनी निजी जागीर मान लिया। एक समय कांग्रेसी छात्र संगठन वामपंथी छात्र संगठनों को चुनौती देता था, लेकिन जैसे ही कांग्रेस और वामपंथी दलों के बीच वैचारिक दूरी घटी, कांग्रेसी छात्र संगठन ने अपने हथियार भारतीय विद्यार्थी परिषद वामपंथी छात्र संगठनों को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। इसे वामपंथी छात्र संगठन सहन नहीं कर पा रहे हैं।

2014 में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद वामपंथी छात्र संगठन और अधिक बेचैन एवं उग्र हो गए। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में एम जगदीश कुमार जेएनयू के कुलपति बने। चूंकि वह न तो वामपंथी खेमे के थे और वाम पृष्ठभूमि वाले इसलिए पहले दिन से उनका विरोध शुरू हो गया। तीन महीने पहले जब जेएनयू की फीस बढ़ाई गई तो उसका उग्र विरोध शुरू हो गया। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने बढ़ी फीस में कटौती कर दी, फिर भी वामपंथी छात्र संगठनों ने धरना-प्रदर्शन जारी रखा।

लोकप्रिय पुस्तक का विमोचन

हार्य-व्यंग्य



पुस्तक मेले में घुसते ही 'वह' दिखाई दिए। मैं कन्नी काटकर निकलना चाहता था, पर उन्होंने मुझे पकड़ ही लिया और पन्नी में लिपटी अपनी किताब पकड़ दी।

फिर फुसफुसाते हुए बोले, 'अब आए हो तो विमोचन करके ही जाओ। तुम मेरे आत्मीय हो। आपदा में अपने ही याद आते हैं।' मैंने भी अनमने ढंग से कहा, 'कोई वरिष्ठ नहीं मिला क्या?' मैं तो आपसे कितना छोटा हूं।' मेरी बात को 'इनरो' करते हुए उन्होंने लंबी आह भरी। बोले कि 'बात यह है कि इस वक्त सीजन बड़ा 'टाइट' चल रहा है। 'कर-कमलों' वाले सभी वरिष्ठ एडवॉंस में 'बुक' हैं। कोई भी 'डेट' खाली नहीं है। बमुश्किल कल एक पेशेवर विमोचक ने हामी भरी थी, परंतु तेरहवीं पुस्तक लोकार्पित करते-करते वह स्वयं इस लोक से 'वॉक-आउट' होने से बचे।

किताब के बारे में वह यह रहस्योद्घाटन भी कर गए कि इसमें लिखी गई कविताएँ बिल्कुल पानी के बत्ताशे की तरह हैं। जुबान में पड़ते ही धुल जाती हैं। साहित्य में यथार्थ के प्रयोग का इससे बेहतर उदाहरण फिलहाल नहीं मिलता। फिर क्या था, प्रकाशक ने इतना सुनते ही उनका गला पकड़ लिया और लेखक ने माथा। बड़ी मुश्किल से उन्हें सुरक्षित गले के साथ प्रशंसकों की भीड़ से बाहर निकाला गया। अच्छी बात यह हुई कि लेखक ने वहीं पर अपनी 56वीं पुस्तक आने की घोषणा कर दी। तब जाकर प्रकाशक संतुष्ट हुआ, लेकिन साहित्य तभी से सड़ने में है।' मैं अब कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। उस 'विमोचन-कांड'



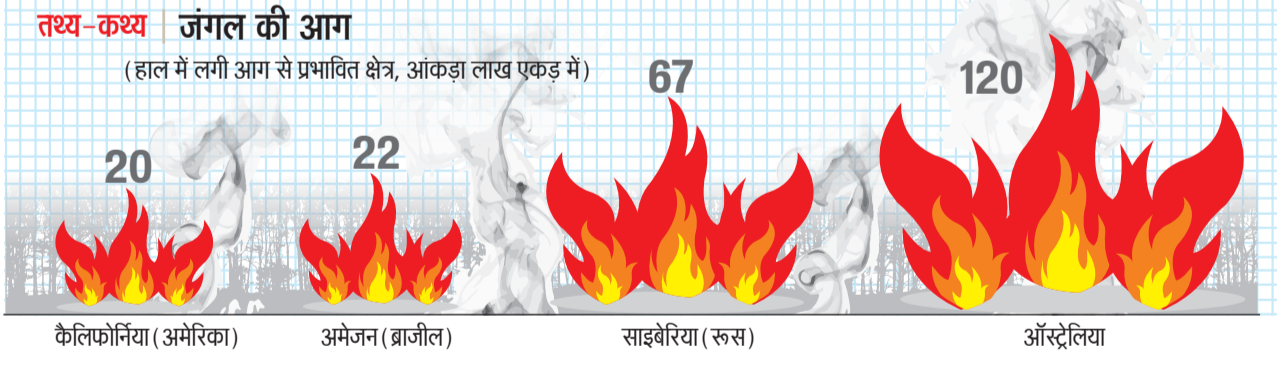
संतोष त्रिवेदी

गुरुजी को विमोचन का इतना अभ्यास था कि किसी भी किताब को देखते ही उनके 'कर-कमल' फड़फड़ाने लगते

से मैंने यही सीखा है। हालांकि दो-तीन बंदों को हमने 'बुक' किया हुआ है, पर बतौर 'बैक-अप' तुम्हें चुन रहा हूं। तुम भले ही वरिष्ठ नहीं हो, पर यह बात भीड़ नहीं जानती। तुम बस मेरे बारे में यह पढ़ देना। यह कहकर उन्होंने मुझे एक पचीं थमा दी। मैंने उसे चुपचाप जेब में रख लिया और आगे बढ़ने लगा। बड़े जतन से मुझे संभलते हुए वह घटना-स्थल तक ले गए। तीन चेहरे पहले से ही वहां कैची लिए तैनात थे। इनमें एक पैदाइशी विमोचक थे और बाकी दोनों उनके चेले। गुरुजी को विमोचन का इतना अभ्यास था कि किसी भी किताब को देखते ही उनके 'कर-कमल' फड़फड़ाने लगते। मेले में यदि किसी दिन वह कोई विमोचन नहीं कर पाते तो उनका शुरार-लेवल बढ़ जाता। इधर किताब में बंधा फीता कटने के लिए तड़प रहा था। जैसे ही चार लोग इकट्ठे हो गए, मुक्ति पाने के लिए पुस्तक तैयार थी। मैंने बिना देरी किए कैची चला दी। इस बीच अनुभवी विमोचक ने सही पैकेट पर वार किया। कई मोबाइल एक साथ

चमक उठे। इस तरह किताब की मुंह दिखाई संपन्न हुई। अब विमोचित किताब पर मेरा मुंह खुलने का समय हो गया। मैंने जब टटोली, पर पचीं नदारद थी। फिर किताब को ले जा उलट-पुलट कर पूरी तरह 'रकेंन' कर लिया। खैर, इसके बाद मेरा वक्तव्य शुरू हो गया, 'मित्रों, कवि ने बिल्कुल नई जमीन पकड़ी है। इसके शीर्षक से ही क्रांति झलकती है। कवि गहन अंधकार में भी आशा का दामन नहीं छोड़ता। वह सुराख जैसी सुरंग में आकाश जैसी स्वच्छंदता की कल्पना करता है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग स्थापित कवियों को दरकिनार कर इस कवि पर गौर करें। साहित्य में प्रयोगवाद की आज से शुरुआत हो रही है। मैं आगे कुछ और बोलता, तभी भीड़ में से भी किसी ने 'प्रयोग' कर दिया। मेज के नीचे रखी समोसे की टोकरी पता नहीं किसने ऊपर रख दी! अचानक सभी साहित्य-प्रेमी समोसों पर टूट पड़े। जैसे-तैसे मेरे हाथ भी एक समोसा लगा पर विमोचित पुस्तक गायब मिली। समोसे और साहित्य दोनों एक साथ निपट रहे थे। दस मिनाट की अफग-तफरी के बाद पुस्तक-लेखक और प्रकाशक पाठकों के इस अप्रत्याशित हमले का जायजा ले रहे थे। मैंने धीरे से लेखक महोदय से पूछा 'कुछ ज्यादा नुकसान हो गया क्या?' अब लेखक जी चौंक पड़े। बोले 'अरे नहीं मित्र, किताब 'हिट' हो गई है। समोसे तीस ही थे, जबकि किताबें पूरी पचास।' मतलब अपनी किताब समोसों से ज्यादा बिकी। तुम्हारा आभारी रहूंगा जीवन भर।' मैं संकोच सहित उस 'आभार' को लेकर मेले से बाहर निकल आया।

response@jagran.com



जलवायु परिवर्तन से उपजा खतरा

मुकुल व्यास

वायुमंडल में कार्बन डाईऑक्साइड के स्तर में वृद्धि से बच्चों की बौद्धिक क्षमता पर असर पड़ सकता है। अमेरिका के कोलोराडो विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने इसके प्रमाण जुटाए हैं। उनके अनुसार वायुमंडल में कार्बन डाईऑक्साइड के बढ़ते हुए स्तर से भविष्य में बच्चों की सोचने-समझने की क्षमता कमजोर पड़ सकती है। इससे पहले हुए अध्ययनों में भी यह बात उभरकर आई थी कि कार्बन डाईऑक्साइड की सामान्य से अधिक मात्रा बच्चों की सोचने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है।

अब शोधकर्ताओं ने यह पता लगाने की कोशिश की है कि वायुमंडल में कार्बन डाईऑक्साइड का बढ़ा हुआ स्तर एक कक्षा के भीतर बच्चे के ज्ञानार्जन को किस प्रकार प्रभावित करता है। पिछले अध्ययनों से पता चला है कि प्रदूषण से बच्चों के कारण सीखने-समझने में दिक्कत आती है, लेकिन स्वच्छ हवा के लिए खिड़कियों को खोलने से यह समस्या काफी हद तक दूर की जा सकती है। इस नए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने इस

कार्बन डाईऑक्साइड की सामान्य से अधिक मात्रा बच्चों में सोचने-समझने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है

बात पर ध्यान केंद्रित किया है कि जब हवा में सामान्य से अधिक कार्बन डाईऑक्साइड होगी तो क्या होगा?

इसे जानने के लिए उन्होंने एक मॉडल में दो परिदृश्यों की कल्पना की। पहले परिदृश्य में बच्चों की सीखने और समझने की क्षमता में वर्ष 2100 तक 25 प्रतिशत की कमी आएगी, क्योंकि उत्सर्जन में कमी के बावजूद छात्रों को सामान्य से अधिक कार्बन डाईऑक्साइड झेलनी पड़ेगी। कार्बन डाईऑक्साइड के स्तर में कोई कटौती न होने वाले दूसरे परिदृश्य में बच्चों की बौद्धिक क्षमता 50 प्रतिशत तक कम होने की आशंका

है। शोधकर्ताओं का कहना है कि सामान्य से अधिक मात्रा में कार्बन डाईऑक्साइड से युक्त हवा के प्रभावों के बारे में यह पहला अध्ययन है। उन्होंने कहा कि उत्सर्जन खत्म करके इस समस्या से निपटा जा सकता है।

इस बीच, कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन को घटाने के लिए कार्बन भंडारण की सीसीएस (कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज) तकनीक अपनाने के सुझाव दिए गए हैं। अभी दुनिया में सिर्फ दो दर्जन सीसीएस प्रोजेक्ट शुरू हो पाए हैं। इसकी वजह उच्च लागत के साथ-साथ तकनीकी उपयोगिता के बारे में अनिश्चितता भी है, लेकिन शोधकर्ताओं का कहना है कि बहुत कम समय में चट्टानों में कार्बन डाईऑक्साइड के भंडारण के लिए कुएँ (इंजेक्शन वेल्) निर्मित किए जा सकते हैं। इससे आइपीसीसी द्वारा निर्धारित लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। आइपीसीसी ने दुनिया में सीसीएस टेक्नोलॉजी के जरिये वर्ष 2050 तक कार्बन उत्सर्जन में 13 प्रतिशत कटौती का लक्ष्य रखा है। अब देखना यह होगा कि दुनिया इस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में कितने प्रयास करती है।

(लेखक विज्ञान के जानकार हैं)

'काम' के बदले समर्थन

केंद्र सरकार ने जबसे रेलवे में कैंडर मर्जर का फैसला किया है तबसे इसके समर्थक और विरोधियों के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। जहाँ अधिकांश यूनियनों ने इस



फैसले के खिलाफ आवाज उठाने का निर्णय किया है, वहीं अफसरों की एक दोयम दर्जे की यूनियन इसके समर्थन में भी उतर आई है। यह अलग बात है कि यह समर्थन किस तरह से हासिल किया गया और आगे इसकी क्या स्थिति होगी, इसे लेकर रेल भवन में तरह-तरह की चर्चाएँ हो रही हैं। जहाँ कुछ लोगों का कहना है कि अब तक उपेक्षित यूनियन के पदाधिकारियों को विशेष अधिकार दिए जाने का वादा किया गया है। वहीं कुछ अन्य लोग मानते हैं कि भंग किए जाने के भय से यूनियन को समर्थन का एलान करना पड़ा है। चर्चा तो यहां तक है कि सरकार से चुनिंदा काम कराने के बाद यूनियन पलटौ भार सकती है। इस बात के संकेत यूनियन के एक पदाधिकारी ने दूसरी बड़ी यूनियन के नेता से मुलाकात में दिए। पदाधिकारी ने कहा कि 'अभी हमें सरकार से कुछ काम करवाने हैं। इसके बाद हम भी आपके साथ खड़े नजर आएंगे'।

शुभ मुहूर्त का इंतजार

राम मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी संभालने वाले ट्रस्ट का

राजरंग

मसौदा बनकर तैयार हो गया है। बस केवल शुभ मुहूर्त का इंतजार किया जा रहा है। बताया जाता है कि अयोध्या डेस्क से जुड़े गृह मंत्रालय के दो वरिष्ठ अधिकारी चुपचाप अयोध्या का दौरा भी कर आए हैं जहाँ उन्होंने इस आंदोलन से जुड़े वरिष्ठ धार्मिक नेताओं से विचार-विमर्श किया है। वैसे तो कहा तो लग भी जा रहा है कि ये लोग ट्रस्ट के मसौदे पर मुहर लगाने गए थे ताकि बाद में कोई विवाद खड़ा न हो। माना जा रहा है कि मकर संक्रांति के बाद कभी भी ट्रस्ट की घोषणा की जा सकती है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सरकार के पास नौ फरवरी तक समय है, लेकिन सरकार तब-तक इंतजार करने के मूड में नहीं है।

दलालों के दलाल

रेलवे में टिकट दलालों के रैकेट को तोड़ने के कई प्रयास हुए, मगर कभी निर्णायक कामयाबी नहीं मिली। अब मौजूदा सरकार भी इसके लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रही है। इसके लिए अगले सप्ताह देशव्यापी अभियान छेड़ा जा रहा है, लेकिन अभियान से पहले ही इस मुहिम के फेल होने की भविष्यवाणियों की जाने लगी हैं। रेलवे के एक अधिकारी ने इसकी वजह भी बता दी। अधिकारी का कहना था कि जिस आरपीएफ को अभियान की कमान सौंपी गई है, उसके क्षत्रपों ने दलाल विरोधी अभियानों को ही कमाई का जरिया बना लिया है। इसके लिए सभी डिवीजनों में आरपीएफ के अधिकारियों ने बाकायदा इलाके बांट रखे हैं। अभियान के नाम पर प्रत्येक इलाके का प्रभारी बड़े दलालों

से मोटी उगाही कर लेता है। इसके बाद अभियान के नाम पर छोटे-मोटे दलालों को पकड़कर तस्वीरें खिंचवा कर मीडिया में वाहवाही लूटी जाती है। आरपीएफ के उत्साही महाविदेशक को इसकी जानकारी नहीं है। यदि उन्हें वास्तव में दलालों पर अंकुश लगाना है तो पहले आरपीएफ के भीतर मौजूद इन 'दलालों के दलालों' की गर्दन पकड़नी चाहिए।

बजट पर टिकी निगाहें

जैसे-जैसे बजट की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे उद्योग जगत में चिंताएँ गहरी जा रही हैं। भले ही कॉरपोरेट टेक्स में कटौती के जरिये इंडिया इंक को भारी भरकम राहत मिली है, लेकिन अर्थव्यवस्था में मांग की कमी से उसके हाथ-पांव फूले हुए हैं। उद्योगपति अपनी निजी राय से लेकर उद्योग चैंबरों तक बातचीत में मान रहे हैं कि बजट में मांग बढ़ाने के ठोस उपाय नहीं हुए तो भविष्य का संकट बढ़ सकता है। दबी जुबान से उद्योग जगत के लोग बजट बनाने वाली टीम की काबिलियत पर भी सवाल उठा रहे हैं। कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़े कई लोग तो यह भी कह रहे हैं कि मंत्रालय में जो लोग बजट पर चिंताएँ गहरी जा रही हैं, वैसे-वैसे उद्योग जगत में चिंताएँ गहरी जा रही हैं। भले ही कॉरपोरेट टेक्स में कटौती के जरिये इंडिया इंक को भारी भरकम राहत मिली है, लेकिन अर्थव्यवस्था में मांग की कमी से उसके हाथ-पांव फूले हुए हैं। उद्योगपति अपनी निजी राय से लेकर उद्योग चैंबरों तक बातचीत में मान रहे हैं कि बजट में मांग बढ़ाने के ठोस उपाय नहीं हुए तो भविष्य का संकट बढ़ सकता है। दबी जुबान से उद्योग जगत के लोग बजट बनाने वाली टीम की काबिलियत पर भी सवाल उठा रहे हैं। कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़े कई लोग तो यह भी कह रहे हैं कि मंत्रालय में जो लोग बजट पर चिंताएँ गहरी जा रही हैं, वैसे-वैसे उद्योग जगत में चिंताएँ गहरी जा रही हैं। भले ही कॉरपोरेट टेक्स में कटौती के जरिये इंडिया इंक को भारी भरकम राहत मिली है, लेकिन अर्थव्यवस्था में मांग की कमी से उसके हाथ-पांव फूले हुए हैं। उद्योगपति अपनी निजी राय से लेकर उद्योग चैंबरों तक बातचीत में मान रहे हैं कि बजट में मांग बढ़ाने के ठोस उपाय नहीं हुए तो भविष्य का संकट बढ़ सकता है। दबी जुबान से उद्योग जगत के लोग बजट बनाने वाली टीम की काबिलियत पर भी सवाल उठा रहे हैं। कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़े कई लोग तो यह भी कह रहे हैं कि मंत्रालय में जो लोग बजट पर चिंताएँ गहरी जा रही हैं, वैसे-वैसे उद्योग जगत में चिंताएँ गहरी जा रही हैं। भले ही कॉरपोरेट टेक्स में कटौती के जरिये इंडिया इंक को भारी भरकम राहत मिली है, लेकिन अर्थव्यवस्था में मांग की कमी से उसके हाथ-पांव फूले हुए हैं। उद्योगपति अपनी निजी राय से लेकर उद्योग चैंबरों तक बातचीत में मान रहे हैं कि बजट में मांग बढ़ाने के ठोस उपाय नहीं हुए तो भविष्य का संकट बढ़ सकता है। दबी जुबान से उद्योग जगत के लोग बजट बनाने वाली टीम की काबिलियत पर भी सवाल उठा रहे हैं। कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़े कई लोग तो यह भी कह रहे हैं कि मंत्रालय में जो लोग बजट पर चिंताएँ गहरी जा रही हैं, वैसे-वैसे उद्योग जगत में चिंताएँ गहरी जा रही हैं। भले ही कॉरपोरेट टेक्स में कटौती के जरिये इंडिया इंक को भारी भरकम राहत मिली है, लेकिन अर्थव्यवस्था में मांग की कमी से उसके हाथ-पांव फूले हुए हैं। उद्योगपति अपनी निजी राय से लेकर उद्योग चैंबरों तक बातचीत में मान रहे हैं कि बजट में मांग बढ़ाने के ठोस उपाय नहीं हुए तो भविष्य का संकट बढ़ सकता है। दबी जुबान से उद्योग जगत के लोग बजट बनाने वाली टीम की काबिलियत पर भी सवाल उठा रहे हैं। कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़े कई लोग तो यह भी कह रहे हैं कि मंत्रालय में जो लोग बजट पर चिंताएँ गहरी जा रही हैं, वैसे-वैसे उद्योग जगत में चिंताएँ गहरी जा रही हैं। भले ही कॉरपोरेट टेक्स में कटौती के जरिये इंडिया इंक को भारी भरकम राहत मिली है, लेकिन अर्थव्यवस्था में मांग की कमी से उसके हाथ-पांव फूले हुए हैं। उद्योगपति अपनी निजी राय से लेकर उद्योग चैंबरों तक बातचीत में मान रहे हैं कि बजट में मांग बढ़ाने के ठोस उपाय नहीं हुए तो भविष्य का संकट बढ़ सकता है। दबी जुबान से उद्योग जगत के लोग बजट बनाने वाली टीम की काबिलियत पर भी सवाल उठा रहे हैं। कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़े कई लोग तो यह भी कह रहे हैं कि मंत्रालय में जो लोग बजट पर चिंताएँ गहरी जा रही हैं, वैसे-वैसे उद्योग जगत में चिंताएँ गहरी जा रही हैं। भले ही कॉरपोरेट टेक्स में कटौती के जरिये इंडिया इंक को भारी भरकम राहत मिली है, लेकिन अर्थव्यवस्था में मांग की कमी से उसके हाथ-पांव फूले हुए हैं। उद्योगपति अपनी निजी राय से लेकर उद्योग चैंबरों तक बातचीत में मान रहे हैं कि बजट में मांग बढ़ाने के ठोस उपाय नहीं हुए तो भविष्य का संकट बढ़ सकता है। दबी जुबान से उद्योग जगत के लोग बजट बनाने वाली टीम की काबिलियत पर भी सवाल उठा रहे हैं। कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़े कई लोग तो यह भी कह रहे हैं कि मंत्रालय में जो लोग बजट पर चिंताएँ गहरी जा रही हैं, वैसे-वैसे उद्योग जगत में चिंताएँ गहरी जा रही हैं। भले ही कॉरपोरेट टेक्स में कटौती के जरिये इंडिया इंक को भारी भरकम राहत मिली है, लेकिन अर्थव्यवस्था में मांग की कमी से उसके हाथ-पांव फूले हुए हैं। उद्योगपति अपनी निजी राय से लेकर उद्योग चैंबरों तक बातचीत में मान रहे हैं कि बजट में मांग बढ़ाने के ठोस उपाय नहीं हुए तो भविष्य का संकट बढ़ सकता है। दबी जुबान से उद्योग जगत के लोग बजट बनाने वाली टीम की काबिलियत पर भी सवाल उठा रहे हैं। कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़े कई लोग तो यह भी कह रहे हैं कि मंत्रालय में जो लोग बजट पर चिंताएँ गहरी जा रही हैं, वैसे-वैसे उद्योग जगत में चिंताएँ गहरी जा रही हैं। भले ही कॉरपोरेट टेक्स में कटौती के जरिये इंडिया इंक को भारी भरकम राहत मिली है, लेकिन अर्थव्यवस्था में मांग की कमी से उसके हाथ-पांव फूले हुए हैं। उद्योगपति अपनी निजी राय से लेकर उद्योग चैंबरों तक बातचीत में मान रहे हैं कि बजट में मांग बढ़ाने के ठोस उपाय नहीं हुए तो भविष्य का संकट बढ़ सकता है। दबी जुबान से उद्योग जगत के लोग बजट बनाने वाली टीम की काबिलियत पर भी सवाल उठा रहे हैं। कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़े कई लोग तो यह भी कह रहे हैं कि मंत्रालय में जो लोग बजट पर चिंताएँ गहरी जा रही हैं, वैसे-वैसे उद्योग जगत में चिंताएँ गहरी जा रही हैं। भले ही कॉरपोरेट टेक्स में कटौती के जरिये इंडिया इंक को भारी भरकम राहत मिली है, लेकिन अर्थव्यवस्था में मांग की कमी से उसके हाथ-पांव फूले हुए हैं। उद्योगपति अपनी निजी राय से लेकर उद्योग चैंबरों तक बातचीत में मान रहे हैं कि बजट में मांग बढ़ाने के ठोस उपाय नहीं हुए तो भविष्य का संकट बढ़ सकता है। दबी जुबान से उद्योग जगत के लोग बजट बनाने वाली टीम की काबिलियत पर भी सवाल उठा रहे हैं। कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़े कई लोग तो यह भी कह रहे हैं कि मंत्रालय में जो लोग बजट पर चिंताएँ गहरी जा रही हैं, वैसे-वैसे उद्योग जगत में चिंताएँ गहरी जा रही हैं। भले ही कॉरपोरेट टेक्स में कटौती के जरिये इंडिया इंक को भारी भरकम राहत मिली है, लेकिन अर्थव्यवस्था में मांग की कमी से उसके हाथ-पांव फूले हुए हैं। उद्योगपति अपनी निजी राय से लेकर उद्योग चैंबरों तक बातचीत में मान रहे हैं कि बजट में मांग बढ़ाने के ठोस उपाय नहीं हुए तो भविष्य का संकट बढ़ सकता है। दबी जुबान से उद्योग जगत के लोग बजट बनाने वाली टीम की काबिलियत पर भी सवाल उठा रहे हैं। कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़े कई लोग तो यह भी कह रहे हैं कि मंत्रालय में जो लोग बजट पर चिंताएँ गहरी जा रही हैं, वैसे-वैसे उद्योग जगत में चिंताएँ गहरी जा रही हैं। भले ही कॉरपोरेट टेक्स में कटौती के जरिये इंडिया इंक को भारी भरकम राहत मिली है, लेकिन अर्थव्यवस्था में मांग की कमी से उसके हाथ-पांव फूले हुए हैं। उद्योगपति अपनी निजी राय से लेकर उद्योग चैंबरों तक बातचीत में मान रहे हैं कि बजट में मांग बढ़ाने के ठोस उपाय नहीं हुए तो भविष्य का संकट बढ़ सकता है। दबी जुबान से उद्योग जगत के लोग बजट बनाने वाली टीम की काबिलियत पर भी सवाल उठा रहे हैं। कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़े कई लोग तो यह भी कह रहे हैं कि मंत्रालय में जो लोग बजट पर चिंताएँ गहरी जा रही हैं, वैसे-वैसे उद्योग जगत में चिंताएँ गहरी जा रही हैं। भले ही कॉरपोरेट टेक्स में कटौती के जरिये इंडिया इंक को भारी भरकम राहत मिली है, लेकिन अर्थव्यवस्था में मांग की कमी से उसके हाथ-पांव फूले हुए हैं। उद्योगपति अपनी निजी राय से लेकर उद्योग चैंबरों तक बातचीत में मान रहे हैं कि बजट में मांग बढ़ाने के ठोस उपाय नहीं हुए तो भविष्य का संकट बढ़ सकता है।